

एआई वाइस बॉट से मरीजों का फीडबैक लेगी योगी सरकार, स्वास्थ्य सेवाओं में होगा सुधार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार तकनीक और नवाचार का इस्तेमाल बढ़ा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नोडल स्टेट हेल्थ एजेंसी ‘साचीज’ द्वारा एआई आधारित वाइस बॉट विकसित किया जा रहा है। इसके माध्यम से आयुष्मान कार्डधारक मरीजों और उनके तीमारदारों से फोन पर सीधे इलाज और अस्पताल में मिले अनुभव का फीडबैक लिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि एआई वाइस बॉट का उद्देश्य केवल मरीजों की राय लेना नहीं, बल्कि प्राप्त प्रतिक्रियाओं का तकनीकी विश्लेषण कर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाना है। इसके जरिए अस्पतालों की निगरानी, शिकायतों के निस्तारण, ऑडिट और उपचार की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वाइस बॉट के माध्यम से इलाज करा चुके मरीजों से फोन पर पूछा जाएगा कि उन्हें आयुष्मान



योजना के तहत उपचार मिला या नहीं। इलाज के दौरान किसी प्रकार की परेशानी हुई या नहीं, अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं कैसी थीं और चिकित्सकों व कर्मचारियों का व्यवहार कैसा रहा, इसकी भी जानकारी ली जाएगी इसके अलावा मरीजों से यह भी पूछा जाएगा कि आयुष्मान योजना के तहत उपचार के बदले उनसे या उनके परिवार से कोई अनधिकृत शुल्क तो नहीं लिया गया। उपचार के बाद मरीज कितना संतुष्ट है, इसकी जानकारी भी फीडबैक के माध्यम से जुटाई जाएगी। इससे मरीजों की समस्याएं और उनका वास्तविक अनुभव सीधे स्वास्थ्य विभाग तक पहुंच सकेगा। साचीज

की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वर्मा ने बताया कि एआई आधारित व्यवस्था के जरिए बड़ी संख्या में मरीजों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का व्यवस्थित विश्लेषण किया जा सकेगा। यदि किसी मरीज द्वारा इलाज न मिलने, अनधिकृत शुल्क वसूले जाने, खराब व्यवहार या अन्य किसी समस्या की जानकारी दी जाती है, तो ऐसे मामलों को संबंधित टीमों तक पहुंचाकर आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल सीमित संख्या में मरीजों से मैनुअल फोन कॉल के जरिए फीडबैक लिया जाता है, जिसमें अधिक समय और मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। एआई वाइस बॉट के जरिए बड़ी संख्या में मरीजों तक पहुंचकर कम समय में अधिक फीडबैक जुटाया जा सकेगा। प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से अस्पतालों की कमियों की पहचान कर स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यक सुधार किए जा सकेंगे।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि एआई वाइस बॉट का उद्देश्य केवल मरीजों की राय लेना नहीं, बल्कि प्राप्त प्रतिक्रियाओं का तकनीकी विश्लेषण कर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाना है। इसके जरिए अस्पतालों की निगरानी, शिकायतों के निस्तारण, ऑडिट और उपचार की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वाइस बॉट के माध्यम से इलाज करा चुके मरीजों से फोन पर पूछा जाएगा कि उन्हें आयुष्मान योजना के तहत उपचार मिला या नहीं। इलाज के दौरान किसी प्रकार की परेशानी हुई या नहीं, अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं कैसी थीं और चिकित्सकों व कर्मचारियों का व्यवहार कैसा रहा, इसकी भी जानकारी ली जाएगी इसके अलावा मरीजों से यह भी पूछा जाएगा कि आयुष्मान योजना के तहत उपचार के बदले उनसे या उनके परिवार से कोई अनधिकृत शुल्क तो नहीं लिया गया। उपचार के बाद मरीज कितना संतुष्ट है, इसकी जानकारी भी फीडबैक के माध्यम से जुटाई जाएगी।

घर से निकलीं युवतियां अचानक गायब, पुलिस महकमे में हड़कंप

- ✦ रहस्य के साये में लापता हुईं चार किशोरियां
- ✦ दो सगी बहनों समेत चार लड़कियों के संदिग्ध हालात में लापता होने से मचा कोहराम
- ✦ सीसीटीवी और सर्विलांस के सहारे तलाश में जुटी पुलिस की कई टीमें

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महमूदाबाद-सीतापुर। कोतवाली इलाके के रेवान गांव से दो सगी बहनों सहित चार किशोरियों और युवतियों के संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक लापता हो जाने का मामला सामने आया है। लापता होने वाली लड़कियों में शन्नो (22), सीमा (14), सवित्रा (15) और सईमा (16) शामिल हैं। शुरूआती छानबीन और सीसीटीवी फुटेजों को खंगालने पर पता

चला है कि ये सभी बस में सवार होकर कहीं बाहर निकली हैं और इस दौरान रामपुर मथुरा इलाके का एक युवक भी पुलिस के रडार पर आया है। परिवारों द्वारा घंटों की गई मशकत के बाद जब उनका कोई सुराग नहीं लगा, तो परिजनों ने स्थानीय कोतवाली में तहरीर दी जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आर्थिक तंगी के चलते काम की तलाश या अन्य किसी एंगल को ध्यान में रखते हुए पुलिस की टीमें पड़ोसी जनपदों के साथ-साथ गैर प्रांतों में

लापता किशोरियों की तलाश के लिए पुलिस की कई विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों व तकनीकी साक्ष्यों की मदद से लगातार छानबीन की जा रही है, और जल्द ही सभी युवतियों को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। वेद प्रकाश श्रीवास्तव, सीओ महमूदाबाद

भी दबिश दे रही हैं और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से उनकी तलाश में जुटी हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक 4 में से दो बच्चियां वापस आ गयी हैं, बचियां वापस कैसे आईं, समाचार लिखे जाने तक जानकारी नहीं मिल पाई है।

गरीबी और संघर्षों को पीछे छोड़ बसन्त कुमार कनौजिया ने हासिल की डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी.) की उपाधि

हरदोई के छोटे से गांव से निकलकर बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय तक का सफर, परिवार की पहली पीढ़ी ने हासिल की उच्च शिक्षा की यह उपलब्धि।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हरदोई। कठिन आर्थिक परिस्थितियों, संघर्ष और सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते हुए हरदोई जिले के मूल निवासी बसन्त कुमार कनौजिया ने बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (Ph.D.) की उपाधि प्राप्त कर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बसन्त कुमार कनौजिया मूल रूप से ग्राम करवा, पोस्ट मल्लावां, जनपद हरदोई के निवासी हैं। अत्यंत साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाले बसन्त ने शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ अपने अध्ययन का खर्च निकालने के लिए कम उम्र से ही संघर्ष किया। उन्होंने कक्षा 10 से ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था और अध्यापन के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखी। लगातार मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर उन्होंने बाबासाहेब भीमराव



अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ से इतिहास विषय में परास्नातक (स्ना.टी.एच.) तथा इतिहास में एम.फिल. की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इसी विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से पीएच.डी. का शोध कार्य पूरा किया। उनका शोध विषय ‘1900-1980’ रहा, जिसमें उत्तर प्रदेश में दलित समाज के सामाजिक-धार्मिक सुधारों का आंदोलनों के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन किया गया है। 29 अगस्त 2026 को बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर

विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में उन्हें इतिहास विषय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (Ph.D.) की उपाधि प्रदान की गई। बसन्त कुमार कनौजिया के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि वे अपने परिवार की पहली पीढ़ी के ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने उच्च शिक्षा के इस मुकाम तक पहुंचकर पीएच.डी. की उपाधि हासिल की है। उनका कहना है कि यह सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि उन विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा है जो सीमित

आर्थिक संसाधनों के बावजूद शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाने का सपना देखते हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, शिक्षकों, शोध निर्देशक प्रो. वी.एम. रवि कुमार, विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी मित्रों, बरिष्ठजनों और शुभचिंतकों को दिया, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में उनका मनोबल बढ़ाया और निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बसन्त कुमार कनौजिया का कहना है कि, ‘संघर्षों ने मुझे रोकने के बजाय और मजबूत बनाया। शिक्षा मेरे लिए केवल व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को समझने और सामाजिक न्याय के लिए कार्य करने का माध्यम है।’ पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचारों, सामाजिक न्याय, शिक्षा और वंचित समाज के इतिहास के अध्ययन एवं लेखन को आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है।

बहु-बेटियों को सुरक्षा और अधिकारों के प्रति किया जागरूक, हिंसा पर चुप्पी न साधने की दी सीख

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मोहनलालगंज। पुलिस उपायुक्त दक्षिणी को. मुश्ताक के निर्देशन में रविवार को मिशन शक्ति केंद्र मोहनलालगंज की टीम ने ‘बहु-बेटी सम्मेलन’ अभियान के तहत थाना क्षेत्र के दीवानगंज गांव में चौपाल लगाकर महिलाओं और बहु-बेटियों को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं महिला अपराधों की रोकथाम के प्रति जागरूक किया। चौपाल के दौरान महिलाओं को घरेलू हिंसा, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना तथा दहेज उत्पीड़न जैसी परिस्थितियों में आत्महत्या जैसा कदम न उठाने की सीख दी गई। विपरीत परिस्थितियों में मानसिक रूप से मजबूत रहते हुए कानून का सहारा लेने



और समय रहते पुलिस से मदद लेने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं अविवाहित युवतियों और पढ़ने वाली छात्राओं से संवाद स्थापित कर उन्हें जल्दबाजी में कोई निर्णय न लेने तथा अपने भविष्य को लेकर सोच-समझकर कदम उठाने के लिए जागरूक किया गया। मिशन शक्ति टीम ने महिलाओं को बताया कि किसी भी प्रकार की हिंसा या प्रताड़ना को सहन करने के बजाय तत्काल पुलिस एवं संबंधित हेल्पलाइन की मदद

लें। टीम ने महिला अपराधों की रोकथाम और आपात स्थिति में सहायता के लिए संचालित हेल्पलाइन नंबर 1090, 181, 1076, 112, 1930, 101, 102 एवं 108 की जानकारी दी। इस दौरान महिलाओं को जागरूकता संबंधी पंपलेट भी वितरित किए गए। साथ ही मिशन शक्ति केंद्र के सीयूजी नंबर की जानकारी देकर जरूरत पड़ने पर पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया। चौपाल के माध्यम से महिलाओं और बेटियों में सुरक्षा के प्रति विश्वास पैदा करने के साथ ही उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और किसी भी विपरीत परिस्थिति में बिना डर कायुन व पुलिस की मदद लेने का संदेश दिया गया।

पुरहिया की बेटी शांभवी दीक्षित ने बढ़ाया गांव का मान, बीबीएयू से मिला गोल्ड मेडल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

निगोहां /लखनऊ। निगोहां क्षेत्र के पुरहिया गांव की होनहार बेटी शांभवी दीक्षित ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के बल पर पूरे गांव और क्षेत्र का मान बढ़ाया है। समाजशास्त्र विभाग में उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए शांभवी को वर्ष 2026 का गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। शनिवार को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय (बीबीएयू), लखनऊ में आयोजित सम्मान समारोह में उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। पुरहिया गांव निवासी पंकज दीक्षित ‘अरुविंद’ की बेटी शांभवी शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही हैं। उनकी माता रीता दीक्षित गृहिणी हैं। साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाली शांभवी ने सीमित संसाधनों के बावजूद



शिक्षा के प्रति अपनी लगन और निरंतर मेहनत को सफलता का आधार बनाया। शांभवी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी 82 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए समाजशास्त्र विषय का चयन किया और विश्वविद्यालय में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया।

समाजशास्त्र विभाग में उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धि के आधार पर विश्वविद्यालय की ओर से उनका चयन वर्ष 2026 के गोल्ड मेडल के लिए किया गया। शनिवार को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में जब शांभवी को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माता-पिता ने बेटी की इस उपलब्धि को अपने जीवन का गौरवपूर्ण क्षण बताया। परिजनों का कहना है कि शांभवी ने अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छाशक्ति से साबित कर दिया कि लगन के साथ कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शांभवी को

गोल्ड मेडल मिलने की खबर जैसे ही पुरहिया गांव और आसपास के क्षेत्र में पहुंची, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों ने शांभवी व उनके परिवार को बधाई दी। लोगों ने कहा कि गांव की बेटी ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि हासिल कर पुरहिया गांव और पूरे निगोहां क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि शांभवी की सफलता क्षेत्र की अन्य बेटियों और विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायी है। उन्होंने यह संदेश दिया है कि ग्रामीण परिवेश और सीमित संसाधनों के बावजूद मेहनत, अनुशासन और शिक्षा के प्रति समर्पण से बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। शांभवी की इस सफलता से जहां पुरहिया गांव गौरवान्वित है, वहीं परिवार में जश्न का माहौल बना हुआ है।

12 सितंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह-समझौते से निस्तारित होंगे वाद

लहरपुर सीतापुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश आशीष जैन के आदेशानुसार एवं सचिव अलोक यादव के निर्देशन में 12 सितंबर 2026, शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में कोतवाली लहरपुर में पीएलबी रहमत अंसारी ने उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्देश्य एवं लाभों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर के साथ-साथ जनपद के समस्त बाढ़ा न्यायालयों एवं तहसील स्तर पर भी किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 प्रक्राम्य लिखत अधिनियम के मामले, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, परिवारिक एवं श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, विद्युत एवं जल बिल, राजस्व, किराया, सुरक्षाधिकार, विशिष्ट अनुतोष तथा बैंकों के प्री-लिटिगेशन मामलों सहित विभिन्न सुलह योग्य मामलों का निस्तारण आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर किया जाएगा। पीएलबी रहमत अंसारी ने आम जनमानस एवं वादकारियों से अपील की कि वे अपने सुलह योग्य मामलों को संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं।

ज्वेलर्स से लाइसेंसी रिवाल्वर, चैन व मोबाइल लूट में नाबालिग गिरफ्तार

.....मामले में चार आरोपी पहले ही जा चुके हैं जेल, तकनीकी व मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पकड़ा 17 वर्षीय किशोर।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मोहनलालगंज।

मोहनलालगंज कस्बे में एक होटल में आयोजित समारोह में शामिल होने गए ज्वेलर्स से लाइसेंसी रिवाल्वर, मोबाइल फोन और गले की चेन लूटने के मामले में फरार चल रहे 17 वर्षीय नाबालिग को मोहनलालगंज पुलिस ने रविवार को पकड़ लिया। पुलिस ने तकनीकी और मैनुअल साक्ष्यों के साथ स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से नाबालिग को हिरासत में लिया है। मामले में पुलिस पहले ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज चुकी है। पुलिस के मुताबिक, बोते सात अप्रैल को ज्वेलर्स हेमंत कुमार सोनी ने मोहनलालगंज थाने में तहरीर देकर बताया था कि एक समारोह में शामिल होने के दौरान उनकी लाइसेंसी रिवाल्वर, मोबाइल फोन और गले की चेन लूट ली गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने रवि सिंह



उर्फ विक्की सिंह, आर्यन सिंह, विशेष त्रिवेदी उर्फ राज पंडित और निखिल सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में रविवार को मोहनलालगंज पुलिस टीम ने तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से फरार चल रहे 17 वर्षीय नाबालिग को पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार, नाबालिग के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

दरगाह बड़े मखदूम साहब में दूसरे दिन हुए कार्यक्रम बड़े मखदूम साहब के जीवन को समझने के लिए दिल कीट आंखों को खोलना होगा:- मुफ्ती किताबुद्दीन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

खैराबाद सीतापुर। स्थानीय दरगाह आलिया सादिया हजरत बड़े मखदूम साहब में तीन दिवसीय 526 वें उस के दूसरे दिन रात में एक जलसे को संबोधित करते हुए मदरसा जामिया आरिफिया सैय्यद सरावा इलाहाबाद से आए मौलाना मुफ्ती किताबुद्दीन ने अपने संबोधन में कहा कि हमें अपने बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करना चाहिए हजरत बड़े मखदूम साहब की जिंदगी को देखें और पढ़ें कि अल्लाह और उसके रसूल को किस दर्जे तक चाहा था जो आज उन्हें यह स्थान प्राप्त है। श्री किताबुद्दीन ने आगे कहा कि बड़े मखदूम साहब की जिंदगी को समझने के लिए दिल की आंखों को खोलना होगा और उनसे जुड़े हुए लोगों से सच्ची मोहब्बत करके उनके हालात को जानना होगा। अल्लाह ने नबियों और रसूलों को दुनिया में भेजा कि मेरे पैगाम



को आम करो, नबियों के बाद औलिया अल्लाह ने इस काम को अंजाम देने के लिए अपनी पूरी जिंदगी उसी में लगा दी। जलसे की अध्यक्षता सज्जादा नशीन शोएब

मियां ने की तथा विशेष रूप से जामिया आरिफिया के सरपरस्त मौलाना शेख अबू मोहम्मद एहसान उल्लाह सफ़वी मौजूद थे, संचालन का कार्य कारी हसन साकिब

उस्मानी ने किया तथा जलसे का शुभारंभ सज्जादा नशीन के छोटे सुपुत्र हफिज अरस्लान हसनी ने तिलावत कुरान पाक से किया।इसके बाद दरगाह हजरत छोटे मखदूम साहब से गागर शरीफ सज्जादा नशीन शोएब मियां,सैय्यद मदनी मियां, सैय्यद शोएब बकाई की मौजूदगी में उठया गया, गागर का रास्ते में कई जगहों पर स्वागत भी किया गया इसी क्रम में हजरत मखदूम बंदगी शाह के आस्ताने पर चादर पोशी दरगाह मतवल्ली इकराम हुसैन की सरपरस्ती में की गई। इसके बाद पूरी रात कव्वाली हुई।इस मौके पर सज्जादा नशीन शोएब मियां, सैय्यद तरीक अहमद किरमानी, मौलाना हुसैन सईदी,मौलाना हसन सईदी सैय्यद सरावां इलाहाबाद,सैय्यद लईक अहमद किरमानी, सैय्यद मोईन अलवी सैय्यद हलाल मुजीबी, सैय्यद लारैब अलवी, डॉक्टर मुहम्मद सिद्दीकी, जावेद मुस्तफा टोटू खान,हाजी सैय्यद इश्तियाक अली वारसीआदि मौजूद रहे।

आरएसएस प्रमुख के बयान पर भारतीय जन समाज पार्टी का हमला, श्वेत पत्र की मांग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। भारतीय जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजमोहन सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के न्यूयॉर्क में दिए गए बयान को लेकर केंद्र सरकार और आरएसएस पर निशाना साधा है। रविवार को जारी बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि विदेश में संविधान की भाषा बोलना और देश में हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को आगे बढ़ाना आरएसएस का दोहरा चरित्र दर्शाता है। बृजमोहन सिंह ने कहा कि भारतीय जन समाज पार्टी संविधान को देश की सर्वोच्च व्यवस्था मानती है। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों से है तथा किसी भी संगठन की विचारधारा को संविधान से ऊपर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने आरएसएस से संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी स्पष्ट प्रतिबद्धता सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति देश के हित में नहीं है। सिंह ने कहा कि देश संविधान के



अनुसार चलेगा और सभी नागरिकों के अधिकारों एवं समानता की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

आरएसएस की संपत्ति और फंडिंग पर श्वेत पत्र की मांग

भारतीय जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरएसएस की वैधानिक स्थिति, संपत्तियों और वित्तीय स्रोतों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने केंद्र सरकार से आरएसएस की संपत्ति और फंडिंग से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने के लिए श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि संगठन की वित्तीय

गतिविधियों और संपत्तियों को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से जांच कराने की मांग भी रखी।

देशभर में आंदोलन की वेतावनी

बृजमोहन सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी आरएसएस प्रमुख के बयान के विरोध में देशभर में अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज उठाएगी और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराएगी।

उन्होंने कहा कि भारत किसी एक संगठन की जागीर नहीं, बल्कि देश के सभी नागरिकों का है। भारतीय जन समाज पार्टी ने संविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपना संघर्ष जारी रखने की बात कही।

संपादकीय



असली घटनाओं पर पर्दा और फर्जी मुकदमों की बाढ़: थाने कब बनेंगे न्याय के केंद्र?



राजीव शुक्ला - (संपादक)

कानून-व्यवस्था किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद होती है। आम नागरिक जब किसी अपराध, विवाद या अन्याय का शिकार होता है तो उसकी पहली उम्मीद पुलिस और थाने से होती है। थाना उसके लिए न्याय की पहली चौखट होना चाहिए। लेकिन जब इसी चौखट पर शिकायत दर्ज कराने से लेकर कार्रवाई तक सवाल खड़े होने लगें, तो आम आदमी के मन में व्यवस्था के प्रति भरोसा कमजोर कहानी तैयार हो जाती है। यही स्थिति को शिकायतकर्ता की सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि उसकी बात सुनी ही नहीं जाती या उसकी शिकायत को गंभीरता से लेने में टालमटोल होती है। दूसरी ओर प्रभावशाली व्यक्ति अपने पहुंच और दबाव के माध्यम से घटनाक्रम को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करता है। यदि पुलिस की प्रारंभिक जांच निष्पक्ष न हो तो वास्तविक घटना धीरे-धीरे छूट जाती है और कागजों में एक दूसरी कहानी तैयार हो जाती है। यही स्थिति को अचलकर विवाद को और जटिल बनाती है। पुलिस के पास जांच, साक्ष्य जुटाने और दोनों पक्षों को सुनने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसलिए किसी भी मामले में केवल शिकायत के आधार पर व्यक्ति को दोषी मान लेना या प्रभावशाली पक्ष के दबाव में कार्रवाई करना न्यायसंगत नहीं हो सकता। किसी निर्दोष व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज होना अपने आप में एक बड़ी परेशानी है। अदालतों के चक्कर, तारीखें, वकील की फीस, सामाजिक बदनामी और मानसिक तनाव-इन सबका बोझ उस व्यक्ति और उसके परिवार को उठाना पड़ता है। मुकदमा अंततः झूठ साबित हो जाए, तब भी वर्षों का समय वापस नहीं आता। यही कारण है कि झूठे और दुर्भावनापूर्ण मुकदमों की समस्या को केवल कानूनी विवाद मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी पर मुकदमा लगाना आसान और उसे झेलना कठिन हो जाए, तो व्यवस्था में संतुलन की आवश्यकता स्पष्ट दिखाई देती है। थाने में भ्रष्टाचार की शिकायतें क्यों उठती हैं? पुलिस व्यवस्था में भ्रष्टाचार का सवाल नया नहीं है। रिस्कव, सिफारिश, राजनीतिक दबाव और प्रभावशाली लोगों के हस्तक्षेप की सही शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं। हालांकि हर पुलिसकर्मी को ध्रष्ट कहना भी उचित नहीं होगा। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी कठिन परिस्थितियों में ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन जहां शिकायतों पर कार्रवाई पैसे या पहुंच से प्रभावित होने लगे, वहां जनता का भरोसा टूटता है। थाने को किसी व्यक्ति की आर्थिक या राजनीतिक हसियत देखकर नहीं, बल्कि कानून और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर काम करना चाहिए। कानून की नजर में गरीब और प्रभावशाली के बीच अंतर दिखाई देने लगे तो कानून का राज कमजोर पड़ता है। किसी मामले में एकआईआर दर्ज होना ही न्याय नहीं है और न ही किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी जांच की अंतिम सफलता। असली परीक्षा निष्पक्ष जांच की है। घटना के साक्ष्य जुटाना, गवाहों के बयान दर्ज करना, सीसीटीवी और डिजिटल प्रमाणों की जांच करना, दोनों पक्षों की बात सुनना और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचना-यही पुलिस जांच की वास्तविक कसौटी होनी चाहिए। यदि जांच मजबूत होगी तो झूठे मुकदमों की गुंजाइश कम होगी और वास्तविक अपराधियों तक पहुंचना आसान होगा। राजनीतिक और सामाजिक दबाव से मुक्त पुलिस जरूरी है। पुलिस पर राजनीतिक या सामाजिक दबाव की चर्चा अक्सर होती है। लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार और प्रशासन के बीच समन्वय जरूरी है, लेकिन कानून लागू करने वाली संस्था की निष्पक्षता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि पुलिसकर्मी को यह डर हो कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने पर उसका तबादला या विभागीय परेशानी हो सकती है, तो स्वतंत्र जांच प्रभावित हो सकती है। इसलिए पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और पेशेवर स्वतंत्रता को मजबूत करना समय की मांग है। सुधार की शुरुआत थाने से होनी चाहिए थाने में शिकायत की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो। शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत की स्थिति की जानकारी मिले। जांच की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की प्रभावी व्यवस्था हो। झूठी शिकायत या दुर्भावनापूर्ण मुकदमे के मामलों में भी कानून के अनुसार जिम्मेदारी तय हो। साथ ही पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण में कानूनी अधिकारों, मानवाधिकारों, डिजिटल साक्ष्यों और निष्पक्ष जांच पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। तकनीक का इस्तेमाल भी पारदर्शिता बढ़ाने में किया जा सकता है। शिकायतों और जांच की डिजिटल ट्रैकिंग, सीसीटीवी की निगरानी और रिकॉर्ड की सुरक्षित व्यवस्था भ्रष्टाचार तथा मनमानी की संभावनाओं को कम कर सकती है। जनता का भरोसा ही पुलिस की सबसे बड़ी ताकत है पुलिस और जनता के बीच संबंध केवल कानून लागू करने वाले और कानून मानने वाले का नहीं होना चाहिए। पुलिस जनता की मुखाक्ष के लिए है और जनता का विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई पीड़ित थाने पहुंचे तो उसे यह भरोसा होना चाहिए कि उसकी बात सुनी जाएगी। उसे यह डर नहीं होना चाहिए कि उसकी शिकायत के बजाय उसी के खिलाफ कोई मामला खड़ा कर दिया जाएगा। लोकतंत्र में कानून का अर्थ केवल अपराधी को सजा देना नहीं, बल्कि निर्दोष की रक्षा करना भी है।



मेघ राशि: आज कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी पुराने काम को पूरा करने का अवसर मिल सकता है। नौकरगोशाला लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

वृषभ राशि: आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। व्यापारियों को रुका हुआ भुगतान मिलने से राहत मिल सकती है। निवेश से जुड़े फैसलों में धैर्य रखें।

मिथुन राशि: आज आपके लिए सक्रियता और सकारात्मक सोच का दिन है। कार्यस्थल पर नए विचारों को महत्व मिल सकता है। किसी विरिष्ट व्यक्ति की सलाह आपके काम आ सकती है।

कर्क राशि: आर्थिक दृष्टि से दिन आपके पक्ष में रह सकता है। नौकरी या व्यापार में कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। पुराने निवेश से लाभ की संभावना है। परिवार के साथ समय बिताते का अवसर मिलेगा और घर का वातावरण सुखद रहेगा।

सिंह राशि: आज आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर मिल सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अधिकारियों के सामने अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें।

कन्या राशि: आज आपको अपने काम की प्राथमिकताएं तय करके आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्षेत्र में पुराने कामों को पूरा करने पर जोर दें। आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है और गैरजरूरी खरीदारी से बचें।

तुला राशि: आज पुराने लंबित कार्यों में प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में किसी नए ग्राहक या संपर्क से लाभ हो सकता है।

वृश्चिक राशि: आज व्यावहारिक सोच के साथ लिए गए निर्णय लाभकारी रहेंगे। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के साथ कुछ अतिरिक्त खर्च भी सामने आ सकता है।

धनु राशि: आज भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय न लें। कार्यक्षेत्र में मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे मिलेगा। व्यापारियों को किसी पुराने सौदे से लाभ हो सकता है। आर्थिक मामलों में जोरिम लेने से बचें।

मकर राशि: आज आर्थिक रूप से दिन मजबूत रह सकता है। नौकरी और व्यापार में सफलता के अवसर मिलेंगे। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। अधिकारियों से संबंध अच्छे होंगे। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

कुंभ राशि: आज आपके सामने कई अवसर आ सकते हैं। लेकिन सभी को एक साथ अपनाने के बजाय प्राथमिकता तय करें। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी को लेकर विचार हो सकता है। व्यापार में लाभ के लिए नई रणनीति बनानी पड़ेगी।

मीन राशि: आज चंद्रमा की स्थिति के कारण भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है। कार्यक्षेत्र में पुराने अशुभ काम पूरे करने पर ध्यान दें। नौकरी में धैर्य से काम लेने पर सफलता मिलेगी।

प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र से कृषकों की जरूरत के अनुरूप मिल रहा है उर्वरक



लखनऊ: उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन का आधार कृषि है। प्रदेश के करोड़ों किसान अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं और कृषि उत्पादन को बेहतर बनाने में समय पर गुणवत्तापूर्ण कृषि निवेश की उपलब्धता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बीज, सिंचाई और कृषि यंत्रों के साथ रासायनिक उर्वरक भी फसल उत्पादन की आवश्यक जरूरतें हैं। ऐसे में किसानों को उनकी आवश्यकता के समय पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराना कृषि व्यवस्था की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है। विशेष रूप से बुवाई और फसल की विभिन्न अवस्थाओं में उर्वरक की मांग बढ़ जाती है। यदि उस समय पर्याप्त उपलब्धता न हो तो किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण और समयबद्ध वितरण की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वर्ष 2026-27 में सहकारिता क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों की अग्रिम भण्डारण योजना के लिए 15,000 लाख रुपये का बजट प्राविधान किया गया है। प्रदेश सरकार किसानों को कृषि सीजन के दौरान उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम स्तर पर तैयारी को महत्व दे रही है। अग्रिम भण्डारण का मूल उद्देश्य यही है कि किसान को उर्वरक की आवश्यकता उस समय हो, जब वह खेत में फसल की तैयारी और उत्पादन से जुड़े कार्य कर रहा हो, और उसी समय सहकारी व्यवस्था के माध्यम से आवश्यक उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके।

कृषि में समय का विशेष महत्व होता है। किसान के लिए बुवाई का समय निकल जाने के बाद उपलब्ध संसाधन भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाते। इसी प्रकार फसल की वृद्धि के विभिन्न चरणों में भी उर्वरक की आवश्यकता होती है। इसलिए उर्वरक की उपलब्धता केवल कुल मात्रा से नहीं, बल्कि उसके सही समय और सही स्थान पर उपलब्ध होने से जुड़ी है। सहकारी क्षेत्र में अग्रिम भण्डारण की व्यवस्था इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर कृषि इनपुट की आपूर्ति को पहले से व्यवस्थित करने का माध्यम बनती है। वर्ष 2026 में निर्धारित 20.45 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के सापेक्ष 30 जून 2026 तक 14.20 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है।

सहकारिता क्षेत्र की विशेषता यह है कि इसकी संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के निकट कार्य करती हैं। यही स्थानीय पहुंच उर्वरक वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब उर्वरक का अग्रिम भण्डारण किया जाता है, तो उसे आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित ढंग से संचालित की जा सकती है। इससे किसान को अपने क्षेत्र में ही कृषि कार्य के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध होने की संभावना बढ़ती है। उर्वरक भण्डारण की व्यवस्था कृषि आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उत्पादन केंद्रों और किसानों के बीच कई स्तरों पर सामग्री के परिवहन, भण्डारण और वितरण की आवश्यकता होती है। इस पूरी प्रक्रिया में यदि किसी स्तर पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध न हो तो इसका असर अंतिम रूप से किसान पर पड़ सकता है। इसलिए सहकारी क्षेत्र में अग्रिम भण्डारण का उद्देश्य आपूर्ति व्यवस्था में निरंतरता बनाए रखना भी है। किसानों की जरूरत के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध कराने में भण्डारण के साथ-साथ वितरण व्यवस्था भी उतनी ही

बदलने का माध्यम है। इससे किसानों को कृषि कार्य के दौरान आवश्यक सामग्री के लिए दूर-दराज के बाजारों पर निर्भरता कम करने में सहायता मिल सकती है।

अग्रिम भण्डारण व्यवस्था का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इससे कृषि सीजन के दौरान अचानक बढ़ने वाली मांग का सामना करने की तैयारी पहले से की जा सकती है। सामान्य परिस्थितियों में उर्वरक की आवश्यकता पूरे वर्ष एक समान नहीं रहती। बुवाई और फसल की विशेष अवस्थाओं में मांग बढ़ सकती है। इसलिए पहले से पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखना वितरण तंत्र पर अचानक पड़ने वाले दबाव को कम करने में सहायक होता है।

सहकारिता के माध्यम से उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने का व्यापक उद्देश्य किसानों को कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों की निर्बाध आपूर्ति उपलब्ध कराना है। कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान की मेहनत के साथ-साथ उचित समय पर उचित कृषि निवेश भी जरूरी है। उर्वरक की अग्रिम उपलब्धता इसी कृषि निवेश व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पूरी व्यवस्था में सहकारी संस्थाएं केवल उर्वरक के भण्डारण और वितरण का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था और आपूर्ति तंत्र के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी मौजूदगी के कारण कृषि संबंधी आवश्यकताओं को स्थानीय स्तर पर समझने और उसके अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराने की संभावना बढ़ती है। यही सहकारी व्यवस्था की वह विशेषता है, जो उसे किसानों के लिए उपयोगी बनाती है।

उर्वरक की अग्रिम भण्डारण व्यवस्था का महत्व केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, इसका वास्तविक उद्देश्य किसान की खेती को समय पर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन की प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखना है। जब उर्वरक पहले से उपलब्ध हो, वितरण तंत्र सक्रिय हो और ग्रामीण स्तर पर सहकारी संस्थाएं किसानों तक सेवाएं पहुंचा रही हों, तो कृषि व्यवस्था अधिक व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ती है। इसी दृष्टि से रासायनिक उर्वरकों की अग्रिम भण्डारण योजना प्रदेश के किसानों को समयबद्ध कृषि निवेश उपलब्ध कराने और सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

संजय कुमार, सहायक निदेशक

ऊर्जा के उजास से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ता प्रदेश



(आंदर अदीब पावेल बन्धु) जिला सूचना अधिकारी

ऊर्जा किसी भी प्रदेश के विकास की वह आधारशिला है जिसके मजबूत होने पर उद्योगों को गति मिलती है खेतों को सिंचाई का संबल मिलता है घरों में रोशनी पहुंचती है और युवाओं के सपनों को उड़ान मिलती है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविधतापूर्ण प्रदेश के लिए विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करना अनिवार्य शर्त है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधारों और दूरगामी नीतियां निर्णयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन परंपरा वितरण उपभोक्ता सुविधाओं और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इन प्रयासों का मूल उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक निर्बाध गुणवत्तापूर्ण और सुलभ विद्युत पहुंचाना तथा ऊर्जा क्षेत्र को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को केवल बिजली उत्पादन तक सीमित न रखते हुए इसे आर्थिक विकास और जनसुविधाओं के व्यापक अभियान के रूप में आगे बढ़ाया है। विद्युत उपकेंद्रों पर तैनात सिव्दा कर्मिकों और अधिकारियों को उर्वरक वसूली के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इसका उद्देश्य विद्युत उपकेंद्रों की राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के साथ उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाना है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व वसूली में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 70,531.26 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली हुई थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 83,564.35 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2023-24 में 1,03,600.48 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी 96,138.68 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली हुई। निश्चित तौर पर यह आंकड़े ऊर्जा क्षेत्र के वित्तीय प्रबंधन और राजस्व संग्रहण को सुदृढ़ बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों को दर्शाते हैं। विद्युत वितरण व्यवस्था में तकनीकी आधुनिकीकरण की विशेष प्राथमिकता दी गई है। आरडीएसएस योजना के अंतर्गत 30 जून 2026 तक 92.90,143 उपभोक्ताओं के संयोजन पर स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। ब्लॉक स्तर तक सभी सरकारी संयोजनों पर स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। लगभग 3,78,690 मीटर वितरण परिवर्तकों तथा 111 केबी पोम्पों में 26,984 स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर व्यवस्था से उपभोक्ताओं को अपनी ऊर्जा खपत पर बेहतर नियंत्रण मिल रहा है। यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप के माध्यम से उपभोक्ता अपनी बिजली खपत की निगरानी करने के साथ रिचार्ज और भुगतान भी कर सकते हैं। मीटर रीडर की आवश्यकता कम होने तथा बिलिंग में मानवीय हस्तक्षेप घटने से त्रुटिरहित बिल उपलब्ध कराने में भी सहायता मिली है। स्मार्ट मीटर को अधिक उपभोक्ता अनुकूल बनाने के लिए डिस्कनेक्शन और री-कनेक्शन पर लागू 50 रुपये का शुल्क समाप्त कर दिया गया है। यह निर्णय उपभोक्ताओं के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।



इसी प्रकार प्री-पेड स्मार्ट मीटरों को पोस्ट-पेड मोड में परिवर्तित करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा और निर्धारित अवधि में भुगतान न होने पर सात दिन बाद संयोजन डिस्कनेक्शन के लिए अर्ह होगा। नए संयोजनों को भी पोस्ट-पेड मोड में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। इससे विद्युत उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा और विकल्प प्राप्त हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बुंदेलखंड क्षेत्र के ग्रामीण निजी नलकूप विद्युत उपभोक्ताओं को एकल फसल की सिंचाई के लिए सोलनल टैरिफ का लाभ तथा अस्थायी विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गई है। यह पहल विशेष रूप से किसानों के लिए उपयोगी है, क्योंकि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में समय पर और किफायती विद्युत आपूर्ति उत्पादन क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। इसी क्रम में लगातार बढ़ती विद्युत दरों के बीच प्रदेश के उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019-20 के बाद विद्युत दरों में वृद्धि नहीं की गई है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं तथा छोटे व्यवसायों को आर्थिक राहत मिली है।

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने नई दिशा निर्धारित की है। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन एनर्जी टैरिफ को उपभोक्ताओं के लिए अधिक आकर्षक बनाया गया है। एचटी उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त ग्रीन एनर्जी टैरिफ को 0.36 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 0.34 रुपये प्रति यूनिट तथा एलटी उपभोक्ताओं के लिए 0.17 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है। इससे हरित ऊर्जा के प्रति उपभोक्ताओं का रुझान बढ़ने की संभावना है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में प्रदेश को नई शक्ति मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों पर लागू वर्तमान टैरिफ को राज्य परिवहन के लिए भी अनुमत्य कर दिया गया है। इससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा और सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बनाने में सहायता प्राप्त होगी। इसी तरह रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए विद्युत दरों को मेट्रो रेल सेवाओं की दरों को समान किया गया है। इससे सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के लिए किफायती और सुगम ऊर्जा व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था के विस्तार को देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं को राज्य सरकार द्वारा उद्योग का दर्जा दिया गया है तथा नीति के अनुरूप इन उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्र में अनुमत्य

सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे उत्तर प्रदेश में तकनीकी निवेश को आकर्षित करने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने तथा प्रदेश को प्रौद्योगिकी आधारित विकास का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। उपभोक्ता सेवाओं में पारदर्शिता और वितरित समाधान के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2025 तक 35 जोन और 75 मंडलों में सीजीआरएफ का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जा रहा है। 17 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन सीजीआरएफ पोर्टल शुरू किया गया है। इससे उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम हुई है। विद्युत बिलों को सरल बनाते हुए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। डिजिटल बिलिंग के लिए ई-मेल क्लॉटर्सपे अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का विकल्प देकर भौतिक बिल वितरण पर निर्भरता घटाई जा रही है। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं।

वर्ष 2016-17 में 5,784 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2026-27 के जून 2026 तक 9,120 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त की गई। पीएलएफ अर्थात् प्लांट लोड फैक्टर में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2016-17 में 68.42 प्रतिशत पीएलएफ के मुकाबले वर्ष 2025-26 में 80.68 प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के जून 2026 तक 83.34 प्रतिशत पीएलएफ प्राप्त किया गया। विद्युत उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वर्ष 2016-17 में 33,556 मिलियन यूनिट ताप विद्युत उत्पादन के मुकाबले वर्ष 2025-26 के मार्च 2026 तक 62,896.143 मिलियन यूनिट तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के जून 2026 तक 16,699.608 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन प्राप्त हुआ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने 25 मई 2025 को अधिकतम 192.1049 मिलियन यूनिट अर्थात् 8004 मेगावाट का रिकॉर्ड विद्युत उत्पादन किया जो 94.61 प्रतिशत पीएलएफ के बराबर रहा। यह उपलब्धि प्रदेश की उत्पादन क्षमता और ऊर्जा संयंत्रों के बेहतर संचालन का प्रमाण है। जल विद्युत के क्षेत्र में भी उपलब्धियों की एक नई इबारत लिखी गई है। वर्ष 2018 से 524.9 मेगावाट क्षमता के जल विद्युत गृहों के संचालन और रखरखाव के साथ नई जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। रिहंद जल विद्युत गृह पिंपरी की

क्षमता को 230 मेगावाट से बढ़ाकर 300 मेगावाट किया गया। सितंबर 2024 में रिहंद जल विद्युत गृह पिंपरी तथा ओबरा जल विद्युत गृह द्वारा पिछले 25 वर्षों के विद्युत उत्पादन का रिकॉर्ड भी तोड़ा गया। नई विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को भविष्य के लिए सुरक्षित किया जा रहा है। 1x660 मेगावाट हरदुआरा तापीय विस्तार परियोजना की इकाई का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 4 जनवरी 2022 को किया गया और फरवरी 2022 से इसका वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ। जवाहरपुर तापीय परियोजना की दोनों इकाइयों से क्रमशः फरवरी और दिसंबर 2024 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ। ओबरा सी तापीय परियोजना की दोनों इकाइयों से भी उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। पनकी तापीय परियोजना की द्वितीय इकाई से अप्रैल 2025 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बुंदेलखंड ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर एक महत्वाकांक्षी पहल है। बुंदेलखंड क्षेत्र में 4,000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क से उत्पादित ऊर्जा की निकासी के लिए 21 परीक्षण उपकेंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। कुल 21 उपकेंद्रों का निर्माण 28 पेंकेजों में किया जा रहा है जिसमें से नौ का ऊर्जाकरण हो चुका है और शेष पर कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान देने के साथ बुंदेलखंड के आर्थिक विकास को भी गति प्रदान कर सकती है।

विद्युत वितरण व्यवस्था को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत पूर्वांचल वाणसी मध्यांचल लखनऊ और दक्षिणांचल आगरा वितरण निगमों में छूटे हुए आवासों के विद्युतीकरण हेतु 917.28 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के अंतर्गत 19,503 मजरे और 2,51,487 घरों को लाभान्वित किया जाना है। इसी प्रकार, धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जनजातीय बहुल ग्रामों में विद्युतीकरण के लिए 31.86 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं जिससे 6,867 घरों एवं सार्वजनिक संस्थानों को विद्युत सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य है।

वास्तव में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र एक व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। एक ओर विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो रही है, तो दूसरी ओर परंपरा और वितरण तंत्र को आधुनिक बनाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर, डिजिटल बिलिंग, ऑनलाइन शिकायत निस्तारण, ग्रीन एनर्जी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और सौर ऊर्जा जैसी पहलें ऊर्जा व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आकार दे रही हैं। किसानों, गरीब परिवारों, छोटे व्यवसायियों जनजातीय समुदायों और दूरदराज के क्षेत्रों तक विद्युत सुविधाओं का विस्तार आधुनिक न्याय की भावना को भी साकार करता है। ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे ये प्रयास बदलते उत्तर प्रदेश की उस विकास यात्रा का प्रतीक हैं जिसमें गांवों से लेकर महानगरों तक विकास की रोशनी पहुंचाने का संकल्प दिखाई देता है। उत्पादन से वितरण तक और परंपरागत दरजों से हरित ऊर्जा तक उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता की नई राह पर अग्रसर है। ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत होती यह आधारशिला आने वाले वर्षों में औद्योगिक विकास रोजगार सृजन कृषि उन्नति और नागरिक सुविधाओं को नई गति प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ऊर्जा के उजास से विकसित आत्मनिर्भर और सशक्त उत्तर प्रदेश के संकल्प को निरंतर मजबूती मिल रही है।

चौधरी व जहाँनें स्वयं दोनों थायों की पुलिस के साथ मिलकर मऊ मिहौनी पुल से आगे बीहड़ क्षेत्र में करीब 3 किमी तक सफा ऑपरेशन चलाया लेकिन फलहाल सफाईतला नही लंग सकी है। थानाधक्षक का कहना है कि जो वायरल वीडियो है उसमें पानी के तेज बहाव में बहकर जा रहे व्यक्ति का फिर पानी में नीचे की ओर है जिससे उसकी पहचान न हो पाने पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, फलहाल सफा ऑपरेशन जारी है। वहीं, वायरल वीडियो को लेकर हरिकिशन के परिजन

लोगों के लिए जीवनभर याद रहने वाला अवसर है। प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा, राहुल आर. भुव्चर तथा अन्य प्रतिभाशाली कलाकारों की टीम द्वारा शानदार प्रस्तुति दी जा रही है। यह नाटक रामायण में वैभव भगवान राम के जीवन, चरित्र, आदर्श और दर्शन को बेहद सुंदर ढंग से जीवंत करता है। मुख्य सचिव ने कहा कि रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि ज्ञान और जीवन की सभी की कला का स्रोत है। यह मनुष्य को सत्य, धर्म, दया, त्याग, कर्तव्य और नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। उन्होंने लोगों, विशेषकर युवा पीढ़ी से अपील की और इसमें दर्शाए गए उच्च जीवन मूल्यों को अपनाकर अपने जीवन को वैभव बनाने का प्रयास करें।